वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की "कार्य परिषद्" की दिनांक 04.01.2024 को सम्पन्न हुई 16 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की कार्य परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 04 जनवरी 2024 पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय के "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेंस हॉल" में मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि.देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नॉकित मा0 सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे:–

(1) प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी.मा.सिं.भ.उ.त.वि.वि. देहरादून। –अध्यक्ष
(2) डॉ मीनाक्षी रावत, एसो. डीन एकेडिमिक, प्रतिनिधि निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की। –सदस्य
(3) श्री श्रीप्रकाश तिवारी, उप सचिव, प्रतिनिधि,सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, –सदस्य
(4) श्री ब्योमकेश दूबे, उपसचिव, प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। –सदस्य
(5)श्रीमती रजनी शुक्ला अपरसचिव न्याय प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
(6)श्री अरविन्द सिंह पांगती, सयुंक्त सचिव, प्रतिनिधि, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड शासन–सदस्य
(7) श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उप सचिव, प्रतिनिधि सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। –सदस्य
(8) श्रीमती किरण भट्ट टोडरिया, पूर्व फिक्की अध्यक्ष उत्तराखण्ड । –सदस्य
(9) श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड। –सदस्य
(10) डॉ0 चन्द्रमोहन सिंह रावत, डीन/प्राचार्य, वी0च0सिं0ग0रा0वि0 एवं शोध संस्थान, श्रीनगर। –सदस्य
(11) डॉ0 डी0पी0 गैरोला, से0नि0 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन। –सदस्य
(12) प्रो0 दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यू–कॉस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड। –सदस्य
(13)प्रो0 शरद प्रधान, निदेशक, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी, गढ़वाल। – सदस्य
(14)प्रो0 एच.एल. मंडोरिया, निदेशक, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इस्टी0टेक0, टनकपुर। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(15)प्रो0 अजीत सिंह, कार्यवाहक निदेशक, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(16) प्रो0 एच.एस. भदौरिया, कार्यवाहक,निदेशक, बौन प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराकाशी, –विशेष आमंत्रित सदस्य
(17)श्री बिक्रम सिंह जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी.मा.सिं.भ.उ.त.वि.वि. देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(18)डॉ0 वी0के0पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी.मा.सिं.भ.उ.त.वि.वि. देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(19)डॉ0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी.मा.सिं.भ.उ.त.वि.वि. देहरादून। –पदेन सचिव

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति महोदय के संक्षिप्त उद्‌बोधन उपरांत कुलसचिव द्वारा मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय का अभार व्यक्त करते हुए मा0 कार्य परिषद के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

बिन्दु सं0–16.01

कार्य परिषद की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चय–

बैठक में सर्वसम्मति द्वारा कार्य परिषद की 15वीं बैठक में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न होने के दृष्टिगत कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–16.02

कार्य परिषद की 15वीं सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय–

मा0 कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा कार्य परिषद की 15 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0:–**16–03**

विश्वविद्यालय में वित्त समिति की दिनांक 14 दिसम्बर 2023 को संपन्न 22वीं बैठक, दिनांक 29 दिसम्बर 2023 को संपन्न परीक्षा समिति की 36 वीं बैठक एवं विद्या परिषद की दिनांक 30 दिसम्बर 2023 को संपन्न 18वीं बैठक के कार्यवृत्तों का अनुमोदन।

विनिश्चय:– वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में सम्पन्न बैठकों के कार्यवृत्तों का विवरण क्रमशः वित्त समिति, परीक्षा समिति व विद्या परिषद के वित्त नियत्रंक, परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हुए लिये गये निर्णयों से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। जिस पर सहमति व्यक्त करते हुए वित्त समिति की दिनांक 14 दिसम्बर 2023 को संपन्न 22वीं बैठक, दिनांक 29 दिसम्बर 2023 को संपन्न परीक्षा समिति की 36वीं बैठक तथा विद्या परिषद की दिनांक 30 दिसम्बर 2023 को संपन्न 18वीं बैठक के कार्यवृत्तों पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं वित्त समिति के बिन्दु 22.02 के निर्णय पर महिद्रा बोलेरो (बेस मॉडल) के स्थान पर महिद्रा बोलेरा (नियो) वाहन क्रय करने का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**16–04**

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में PG Diploma in Cyber Security Program संचालित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में साईबर क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ मिलकर PG Diploma in Cyber Security संचालन किये जाने एवं विश्वविद्यालय में संचालित B.Tech Cyber Security का द्वितीय वर्ष से चौथें वर्ष तक के कतिपय विषयों को Field Experts से अध्यापन के सम्बन्ध में वित्त समिति एवं विद्या परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदनानुसार इनके संचालन पर सहमति व्यक्त करते हुए माननीय कार्य परिषद द्वारा चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु सं0:–**16–05**

विश्वविद्यालय में विधि परामर्शदाता तथा एक सलाहकार (वित्तीय/तकनीकी) की नियुक्ति किये जाने हेतु मा0 कार्यपरिषद के सदस्यों विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः– विश्वविद्यालय में विधि परामर्शदाता तथा एक सलाहकार (तकनीकी) की नियत रू0 35000/– प्रतिमाह की दर पर आउटसोर्स के माध्यम से पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्त पोषित व्यवस्था में रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु सं0:–**16–06**

शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को विश्वविद्यालय की अनापत्ति के अभाव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की सूचना।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून से संबद्ध निजी संस्थान शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को विश्वविद्यालय की अनापत्ति के अभाव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद के विगत निर्णयानुसार कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा संतोष व्यक्त किया गया तथा इसी कम में अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड व पूर्व अध्यक्ष फिक्की द्वारा भी मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया वह भी अपने स्तर से यू0जी0सी0 को शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु संबद्धकारी विश्वविद्यालय की समुचित भूमिका, स्वायत्त संस्थान के शैक्षणिक कार्यकमों के संचालन हेतु पत्र प्रेषित करेगी। उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सहमति दी गयी।

बिन्दु सं0:–**16–07**

विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों को स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा एवं विचारार्थ।

विनिश्चयः— वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून से संबद्ध संस्थानों को उनकी मांग पर स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जितने अवधि तक के लिए नियामक इकाई यथा एआईसीटीई / पी.सी. आई. / बी.सी.आई. द्वारा सम्बद्धता दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी उतने ही अवधि तक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा भी सम्बद्धता दिये जाने पर विनियमावली में स्थायी संबद्धता के प्राविधान होने पर विचार कर सकता है। उक्त पर माननीय कार्य परिषद द्वारा सहमति दी गयी।

बिन्दु सं0:—**16—08**

विश्वविद्यालय में टेस्टींग एवं कन्सलटैंसी नियमावली पर विचार व अनुमोदन।

विनिश्चयः— वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में टेस्टींग एवं कन्सलटैंसी नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद को विस्तृत रूप से इसके बारे में अवगत कराया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा विचारोपरांत विश्वविद्यालय में ''टेस्टींग एवं कन्सलटैंसी नियमावली'' पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक—6)

बिन्दु सं0:—**16—09**

विश्वविद्यालय के सम्बद्ध / परिसर संस्थानों में ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024—25 से Under Graduate Course in Computer Application and Management (BCA/BBA/BMS/BBM) पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चयः— वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के संबद्ध संस्थानों, परिसर संस्थानों व नवीन संस्थान हेतु ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024—25 से Under Graduate Course in Computer Application and Management (BCA/BBA/BMS/BBM) पाठ्यक्रमों को नियमानुसार सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। चर्चा उपरांत मा0 कार्यपरिषद द्वारा

ए.आई.सी.टी.ई. के मानकानुसार/प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**16–10**

हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी एण्ड रिसर्च, देहरादून द्वारा अनर्ह छात्रों को बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी एण्ड रिसर्च, देहरादून द्वारा अनर्ह छात्रों को बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में संस्थान पर रू0 पॉच लाख का अर्थदंण्ड अधिरोपित किये जाने के विद्या परिषद के निर्णय पर कार्यवाही हेतु मा0 कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया।

बिन्दु सं0:–**16–11**

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों को राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध संस्थानों को राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा आतिथि तक निर्गत सम्बद्धता आदेश मा0 कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा साथ ही यह निर्णय लिया गया कि सभी संस्थानों की संबद्धता आवेदन में प्रस्तुत समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाये ताकि हितधारकों को भी सूचनाएं पारदर्शी रूप से देखा जा सके।

बिन्दु सं0:–**16–12**

विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान नन्हीं परी सीमान्त इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पिथौरागढ़ में निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया नये सिरे से कराये जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के कैम्पस संस्थान नन्हीं परी सीमान्त इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पिथौरागढ़ में पूर्व में चयन

प्रकिया पूर्ण कर नियुक्त किये गये प्रो0 वी0के0सिंह द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी योगदान न दिये जाने के दृष्टिगत उनकी नियुक्ति को शासन के पत्रानुसार निरस्त मानते हुऐ निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्व मे प्रदत्त कार्य परिषद के अनुमोदनानुसार विगत की भांति नये सिरे से कराये जाने पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**16–13**

विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ फॉर्मेसी में असिस्टेण्ट प्रोफेसर Short Term Engagement 11 माह हेतु अस्थायी व स्ववित्त पोषित आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के फैकल्टी ऑफ फॉर्मेसी में बी0फार्म पाठयकम के सत्र 2023–24 से संचालित होने दृष्टिगत फार्मेसी कॉउसिंल ऑफ इंडिया के मानकों की पूर्ति हेतु तीन असिस्टेण्ट प्रोफेसर Short Term Engagement 11 माह हेतु पूर्णतः अस्थायी व स्ववित्त पोषित आधार पर ए0आई0सी0टी0ई0 / PCI के मानकानुसार ₹ 57700 / –प्रतिमाह में विगत में कार्य परिषद् के अनुमोदनानुसार पूर्व में अपनायी गई प्रकियानुसार रखे जाने पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**16–14**

विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेण्ट प्रोफेसर रखे जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में एम0टेक0 / एम0फार्मा0 / एम0बी0ए0 / बी0टेक0 / बी0फार्म0 आदि पाठयकम को संचालित किया जा रहा है। उक्त पाठयकमों हेतु विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेण्ट प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रतिनियुक्ति पर एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेण्ट प्रोफेसर कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग में नियमित नियुक्ति होने तक रखे जाने पर सहमति दी गयी तथा

एम0बी0ए0 के लिए शिक्षको के पदो के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए तथा तात्कालीक व्यवस्था में छात्र हित के दृष्टिगत दो सहायक प्रोफेसर (11 माह के Short Term Engagement पर) पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था व स्ववित्त पोषित स्वरूप में एम0बी0ए0 में रखे जाने की स्वीकृति मा0 कार्यपरिषद द्वारा दी गयी।

बिन्दु सं0:–**16–15**

विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों में सत्र 2024–25 से नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के परिसर संस्थानों में सत्र 2024–25 से निम्न नवीन पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित स्वरूप में संचालित करने पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिसर संस्थान का नाम	पाठयक्रम	क्षमता
नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़।	बी0सी0ए0	60
आई0टी0 गोपेश्वर जनपद चमोली।	बी0सी0ए0	60
डब्लू0आई0टी0 देहरादून।	बी0सी0ए0	60
डॉ0एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर।	बी0सी0ए0	60
आई0टी0 बौन उत्तराकाशी।	बी0सी0ए0	60
	बी.टेक. (सिविल इंजी)	30

बिन्दु सं0:–**16–16** विश्वविद्यालय में एम0टेक0 (पार्ट टाइम) संचालन हेतु ऑर्डिनेंश का अनुमोदन।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के परिसर में एम0टेक0 (पार्ट टाइम) संचालन हेतु विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित ऑर्डिनेंश, शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क लिये जाने के प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।(संलग्नक–7)

बिन्दु संख्या–16.17

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवीन विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन की सूचना मा0 कार्य परिषद को सूचनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवीन विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2005 की धारा–2 में संशोधन की अधिसूचना संख्या–372/ XXXVI(3)/2023/45(i)/2023 दिनांक 17 अक्टूबर 2023 से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई, इस कम में विश्वविद्यालय द्वारा विधि के नये संस्थानों/पाठयकमों में बार कॉउसिंलिग ऑफ इंडिया के मानकानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक–8)

बिन्दु संख्या–16.18

गर्वमेंट इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, नरेन्द्रनगर (पूर्ववर्ती राजकीय पॉलीटेक्निक, नरेन्द्रनगर) को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 परिषद को सूचनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– गर्वमेंट इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, नरेन्द्रनगर (पूर्ववर्ती राजकीय पॉलीटेक्निक, नरेन्द्रनगर) को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए इस हेतु विश्वविद्याल द्वारा की जा रही कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–16.19

विश्वविद्यालय में 2017 में पी.एच.डी. प्रवेश पर गतिमान खुली सतर्कता जांच के दृष्टिगत 2017 मे प्रवेशित शोधार्थियों की RDC वावत मा. उच्च न्यायालय के आदेश के संबन्ध में मा0 कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्तावः– मा. कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि वर्ष 2017 में सम्पन्न Ph.D प्रवेश पर राज्य सरकार द्वारा संस्थित खुली सतर्कता जांच गतिमान होने के कारण इन शोधार्थियों की RDC वाधित है। मा. उच्च न्यायालय के दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय को इन शोधार्थियों की RDC बैठक कराये जाने हेतु निर्देश दिए गये है। संपूर्ण प्रकरण मा. कार्य परिषद् के समक्ष रखा गया जिसमें मा0 सदस्यों द्वारा शासन को समय पर कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने तथा शासन के निदेशानुसार कार्यवाही करने एवं अन्यथा की दशा में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस0एल0पी0 दाखिल किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

बिन्दु संख्या–16.20

विश्वविद्यालय परिसर में Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) के मध्य प्रस्तावित एम0ओ0ए0 के माध्यम से विभिन्न सार्टिफिकेट कोर्स विश्वविद्यालय एवं सीडैक के शेयरिंग बेसिस पर संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष सैद्धान्तिक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–विश्वविद्यालय तथा Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) के मध्य हुये एम0ओ0ए0 किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया जिस पर माननीय कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की 18 वीं बैठक के बिन्दु 18.13(3) के अनुसार कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–16.21

विश्वविद्यालय में निम्न संस्थाओं के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद के समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय में निम्न संस्थाओं के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किये गये/किये जाने प्रस्तावित हैः–

1- Cranes varsity, Banglore. MOU संपादित।
2- Campus Technolgy (Times Internet, Times of India group), New Delhi- MOU होना है।
3- Centre for training and research in financial administration, Sudhowala, Dehradun- MOU होना है।
4- SPNG Group - MOU होना है।

उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या– 16.22

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2030/XXX(4)/2022–02(16)/2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्तें की दरों को विश्वविद्यालय में पुनरीक्षित करते हुए विश्वविद्यालय में लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों, सेमिनार, कार्यक्रमों आदि हेतु आमंत्रित किये जाने वाले महानुभावों हेतु यात्रा भत्ता की दरें पुनरीक्षित नही होने के कारण प्रदेश के दूरस्थ स्थानों व अन्य प्रदेशों से आमंत्रित महानुभावों व विषय–विशेषज्ञों के द्वारा स्वयं के वाहन से यात्रा पर यात्रा–भत्ता को लेकर प्रतिभाग करने में असमर्थता व्यक्त की जाती रही है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में यात्रा भत्ता हेतु पूर्व निर्धारित दरों को पुनरीक्षित किये जाने पर विचार कर **उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2030/XXX(4)/2022–02(16)/2022** दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु निर्धारित यात्रा भत्ता की दरों के अनुसार कार्य हित में विश्वविद्यालय में भी यात्रा भत्ता की दरें लागू किये जाने पर मा0 कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–16.23

महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका के कम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/08/2023, 10/11/2023 एवं 22/11/2023 अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र 2024–25 में संस्थान में एम0बी0ए0 व एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में छात्राओं के प्रवेश हेतु संस्थान का नाम विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जोड़ने का प्रकरण मा0 कार्य परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्यचः– मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि राजभवन, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून को शैक्षिक सत्र 2021–22 में एम0बी0ए0 व एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की गयी हैः–

1. संस्थान को संचालित करने वाली "महादेवी कन्या पाठशाला कॉलेज सोसाईटी" का नवीनीकरण वर्ष 2015 में समाप्त हो चुका है और नवीनीकरण का प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णय के आलोक में सोसाईटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही करते हुए नवीनीकरण सम्बन्धी कृत

कार्यवाही से सचिवालय को अवगत कराये। सोसाईटी के नवीनीकरण के अभाव में उसके द्वारा संचालित संस्थान के आगामी सत्रों की सम्बद्धता पर विचार नही किया जायेगा।

2. यह भी कि जब तक "महादेवी कन्या पाठशाला सोसाईटी" का नवीनीकरण नही किया जाता तब तक नवीन शैक्षिक सत्र के लिए छात्र–छात्राओं के प्रवेश प्रकिया आरम्भ न की जाये।

तत्कम में प्रश्नगत प्रकरण पर विश्वविद्यालय की मा0 कार्यपरिषद् की 14वीं बैठक के बिन्दु संख्या 14:30 में निम्न्वत निर्णय लिये गये है:–

1. राजभवन, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 विश्वविद्यालय को संस्थान में सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रकिया उपरान्त प्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान के शैक्षिक सत्र 2022–23 के प्रवेश, अस्थाई सम्बद्धता, परीक्षा आदि कार्यो को कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. 2023–24 में संस्थान के सोसाईटी से सम्बन्धित विवाद के प्रकरण का निराकरण होने तक संस्थान द्वारा कोई भी नवीन प्रवेश न लिये जाने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संस्थान के शैक्षिक सत्र 2023–24 के प्रवेश, अस्थाई सम्बद्धता आदि पर किसी प्रकार की कार्रवाई न किये जाने का निर्णय लिया गया है

3. संस्थान के सोसाईटी से सम्बन्धित प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के प्रवेश, अस्थाई सम्बद्धता आदि पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त के कम में संस्थान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या WPMS No. 2013 of 2023 पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 10/08/2023 में निम्न्वत आदेश पारित किये गये है:– **In view of the above, having considered, as an interim measure, till the next date of listing, the operation and effect of the impugned orders shall remain in abeyance."**

इसी कम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की डबल बैंच में स्पेशल एप्लीकेशन न0 332/2023 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10/11/2023 द्वारा खारिज कर दिया गया।

तत्क्रम में संस्थान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में, नैनीताल में अवमानना याचिका (Contempt Petition) 308/2023 दायर की गयी, जिसकी सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 22/11/2023 को निम्नवत आदेश निर्गत किया गयाः–

" Issue notices to respondent to file the response as to why he may not be punished for non compliance of the order passed by this Court vide order dated 10.08.2023 passed in Writ petition (M/S) No. 2013 of 2023, Mahadevi Kanya Pathshala Society and another versus State of Uttarakhand and others.

उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/08/2023, 10/11/2023 एवं 22/11/2023 के अनुपालन में संस्थान **महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून** में आगामी शैक्षिक सत्र 2024–25 में एम0बी0ए0 व एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में छात्राओं के प्रवेश हेतु संस्थान का नाम विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जोड़ने को प्रकरण पर मा0 कार्य परिषद् में चर्चा हुई तद्क्रम में माननीय कार्य परिषद द्वारा राजभवन व तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन के दिशा निर्देशानुसार कार्य किये जाने अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर करने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देशित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या– 16.24 अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या– 16.24(1)

मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय उत्तराखखण्ड द्वारा अपने विवेकाधीन कोष से वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून को प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 1,25000.00 की धनराशि प्रदान किये जाने की सूचना मा0 कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड द्वारा अपने विवेकाधीन कोष से वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून को "विश्वविद्यालय की प्रकियाओं के डिजिटलीकरण एवं निर्गत की जाने वाली अंकतालिका एवं उपाधि में सिक्योरिटी फीचर्स का उपयोग" के सफल प्रयास हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 1,25000.00 की धनराशि प्राप्ति पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या– 16.24(2)

विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2018 में कतिपय संशोधित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय–

विश्वविद्यालय के प्रथम नियमावली 2018 में कतिपय संशोधित किये जाने का प्रस्ताव पूर्व में सम्पन्न कार्य परिषद की 13 वीं बैठक के विनिश्चय के कम में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उक्त के कम में शासन के पत्र दिनांक 18 अगस्त 2023 में अपेक्षा की गयी है कि शासनादेश संख्या–564/2023/XLI-A-65/2022(ई–38893) दिनांक 09.05.2023 में लिय गये निर्णयानुसार तथा विश्वविद्यालय के अधिनियम/विनियमावली के अनुसार नियमावली में संशोधित किये जाने के संबंध प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है। प्रकरण में चर्चा के बाद मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नवत् पुनरीक्षित संशोधन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

वर्तमान व्यवस्था	पूर्व में कार्य परिषद की 13वीं बैठक में अनुमोदित	वर्तमान में शासन द्वारा 18 अगस्त 2023 में की गई अपेक्षा के कम में पुनरीक्षित प्रस्तावित संशोधन
विश्वविद्यालय, संस्थाओं के शैक्षिक वर्गों के लिए सीधी भर्ती हेतु विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 11.02–2 एवं 11.12–2 में उक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार व्यवस्था हैः– **11.02–2** :– संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती पूर्णतः योग्यता पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम चयनोपरान्त पदत्त संस्तुति के आधार पर की जायेगी। **11.12–2** विश्वविद्यालय, संस्थाओं या उसके अध्यापकों के लिए चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) /विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों पर की जायेगी।	**विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 11.02–2 एवं 11.12–2** **11.02–2** :– संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती पूर्णतः योग्यता पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा विभिन्न नियामक संस्थाओं के अनुसार गठित चयन समिति की प्रदत्त संस्तुति के आधार पर कार्य परिषद के द्वारा की जायेगी। **11.12–2** संस्थाओं या उसके अध्यापकों के लिए चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC)एवं अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा की जायेगी।	**विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 11.02–2 एवं 11.12–2** **11.02–2** :– विश्वविद्यालय तथा इसके परिसर संस्थानों में उपलब्ध संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती पूर्णतः योग्यता पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा विभिन्न नियामक संस्थाओं के अनुसार गठित चयन समिति की प्रदत्त संस्तुति के आधार पर कार्य परिषद के द्वारा की जायेगी। **11.12–2** विश्वविद्यालय एवं उसके परिसर संस्थानों के अध्यापकों के लिए चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) /विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) फार्मेसी काउसिंल ऑफ इंडिया एवं अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा की जायेगी।

वर्तमान व्यवस्था	पूर्व में कार्य परिषद की 13वीं बैठक में अनुमोदित	वर्तमान में **शासन द्वारा 18 अगस्त 2023 में की गई अपेक्षा के कम में** पुनरीक्षित **प्रस्ताव प्रस्तावित संशोधन**
शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु विनियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु 11.12–3–(3) में एक अतिरिक्त बिन्दु निम्नानुसार जोड़ा जाना प्रस्तावित है:–	शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी **भर्ती** विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए अर्हतायें/ योग्यतायें राज्य सरकार के नियमानुसार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग/अन्य राज्य सरकार की चयन ऐजेंसियों की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा की जायेंगी। सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, आरक्षण समय –समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।	शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी **भर्ती** विश्वविद्यालय तथा इसके परिसर संस्थानों में शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए अर्हतायें/ योग्यतायें राज्य सरकार के नियमानुसार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग/अन्य राज्य सरकार की चयन ऐजेंसियों की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा की जायेंगी। सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, आरक्षण समय –समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

बिन्दु संख्या– 16.24(3)

डॉ अंकिता बिष्ट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून के अतिरिक्त असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) के संबंध मा0 कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

डॉ अंकिता बिष्ट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक सेन्टर फॉर कंपोजिट मैटेरियल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर यू0एस0ए0 में पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम हेतु असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) स्वीकृति किया गया था। डॉ. अंकिता बिष्ट द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से दिनांक 31 सितम्बर, 2024 तक सेन्टर फॉर कंपोजिट मैटेरियल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर यू0एस0ए0 में पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम हेतु अतिरिक्त असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) की स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में नियमित शिक्षकों की अत्यधिक कमी तथा छात्रहित में विस्तृत चर्चा के उपरांत डॉ अंकिता बिष्ट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून को अपवाद स्वरूप अब तक की बिना पूर्वानुमति के अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की गयी तथा 31 जनवरी 2024 तक कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

अन्त में समस्त सम्मानित सदस्यों एवं मा0 कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रो,सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव,
वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि.

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(रजनी शुक्ला)
अपर सचिव, न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(दीप्ती मिश्रा)
उप सचिव
वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(डॉ.मीनाक्षी रावत)
निदेशक, प्रतिनिधि
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की

(डॉ0 चन्द्रमोहन सिंह रावत)
डीन / प्राचार्य
वी0च0सिं0ग0रा0वि0 एवं शोध संस्थान,श्रीनगर,

(पंकज कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष,
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड,

(किरन भट्ट टोडरिया)
पूर्व अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पूर्व फिक्की अध्यक्ष

(प्रो0 दुर्गेश पंत)
महानिदेशक
यू0–कॉस्ट, देहरादून

(प्रो0 शरद प्रधान)
निदेशक
टी.एच.डी.सी–आई.एच.ई.टी.नई टिहरी,

(डॉ0 डी0पी0 गैरोला)
से0नि0 प्रमुख सचिव न्याय
उत्तराखण्ड शासन,

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव
तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन,

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति,

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तर ... ौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 ... र्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)
Veer Madho Singh Bhandari ... nd Technical University
(Formerly Uttarakhand Technical University Est... 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnaga... a, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No.0135-2774067 Web... tech.ac.in

Ref.No............V.M.S.B/U.T.U/2023 Date..................

Rules for Testing and Consultancy

All full time and academic staff shall be permitted to engage themselves in testing and consultancy work to such an extent that it will not interfere with the discharge of their normal duties. However, in exceptional cases the contractual faculty may also be permitted for engaging in testing and consultancy work with permission of Vice Chancellor of Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, here after referred to as University The following are the rules for carrying out Testing & Consultancy work in the University and its Institutions . These rules for testing and consultancy can be revised by the Testing & Consultancy committee with the approval of Vice Chancellor of the University.

1. Testing & Consultancy Committee-

There shall be Testing & Consultancy (T&C) Committee to decide the matter of testing and consultancy work. The T&C committee will be consisting of the following members who will decide about various issues as may be enunciated hereafter which may arise in management and implementation of testing / consulting project and utilization of the saving there from-

A) Nominee of the Vice Chancellor not below rank of Professor - Chairman
B) Any two faculty members not below rank of Associate Professor, nominated by Vice Chancellor - Members
C) Finance Controller - Member
D) Registrar - Member Secretary

The committee may decide any other rules required and rates of the testing etc. in case of requirement. The committee may also consider the expertise required to accomplish the consultancy work in case of any dispute. The recommendation of the committee will be approved by Vice Chancellor of the University. All types of testing & consultancy work with due certification must be digitally signed by the concerned faculty /Principal Investigator (PI) for its validity in all respect. In case of any dispute the decision of Vice Chancellor of the University shall be binding to all.

2. Types of Consultancy Projects-

A- Type -I Consultancy Projects-

All Consultancy Projects without use of University laboratory/ workshop facilities will be classified as type -1 Consultancy Projects which is to be normally done after University working hours.

B- Type -II Consultancy Projects-

Consultancy Projects involving use of University/Institutions laboratory/ workshop facilities will be treated as Type-II consultancy projects. Such project will cover field testing and field measurements. Calibration of equipment/instruments and testing of material/equipment in laboratory / field which can be completed within the University hours or beyond it.

Note- a)- In case of multi-disciplinary/inter departmental project, a single project can be divided into sub projects of the same type on mutually agreed terms between the concerned department duly authorized by T&C committee.

b)- Any controversy arising out of the assignment of consultancy work or non-acceptance of any consultancy project is to be referred to the T&C committee. The Testing & Consultancy (T &C) committee is also authorized to consider prestige of project proposals received by the University and take appropriate decision to accept such project to be carried out on a consultancy basis.

c) All decisions of T&C committee will require approval of Vice Chancellor.

3. Charges for Consultancy Projects-

A. The total agreed charges of consultancy project will consists of the University share, actual expenses and the remuneration to be distributed to the associated faculty investigator and associate staff.

B. The actual expenses should cover the following costs related to the project-

- Permanent equipment to be procured/fabrication of equipment of project.
- Consumable materials.
- Travel expenses in connection with the project work.
- Computational or other charges which the principal Investigator (PI) may have to pay to the University or any other outside agency in the course of the execution of work.
- Contingency expenses to cover cost of supplies, preparation of report, typing work, drawing, drafting, stationary, literature, postage, courier, etc.
- Expenses for work to be carried out on payment basis e.g. remuneration to the students involved etc.
- The principal investigator may engage University Student as Student Assistant for consultancy work on payment of Rs. 100.00 per hour subject to maximum of 50 hours per month which may be revised by Vice Chancellor based on requirement.
- Occasional expenses incurred on reasonable hospitality not exceeding Rs. 250.00 per meal and Rs. 100.00 per head for snacks etc. in connection with the consultation work can be charged as the expenses which may be revised by the Vice Chancellor based on the requirements and recommendation of T&C committee.

4- Consultancy/Testing Fee-

The Consultancy/Testing fee will depend upon several factors such as time spent importance of advice and experience of the faculty. While estimating the consultancy fee chargeable to the client. Principal investigator should keep in mind that only part of the total fee is available for distribution amongst the faculty, staff and students as applicable. The remuneration will be paid to the faculty/ staff as per norms approved by the University on the recommendation of the PI.

5- Realization of Consultancy/Testing Fee-

The entire fee in connection with consultancy/testing work is to be deposited by the client in the University account, before the work commences. In exceptional cases where the work is started with only partial cost deposited in advance, the arrangement of subsequent receipt of fund from the client has to be clearly spelled out in advance and be duly approved by the Vice Chancellor of the University.

6- Type of Consultancy/Testing Funds-

There will be a UNIVERSITY CORPUS FUND for the University share in each consultancy project. Complete amount of consultancy (Both types) fee will be deposited by the client in the University account, in name of FINANCE CONTROLLER while approved percentage of share of University will be deposited in the account of UNIVERSITY CORPUS FUND at the time of distribution of consultancy/testing fee.

B) UNIVERSITY CORPUS FUNDS (U.C.F) will be divided equally in UNIVERSITY DEVELOPMENT FUNDS (U.D.F) and INSTITUTE DEVELOPMENT FUNDS (I.D.F). The use of U.D.F will be decided by the Vice Chancellor for the development of the University in following areas such as:

- Purchase of equipment and consumables for research and academic works.
- Travel for PI/Students/co-authors/collaborators (with in the country and abroad) for attending conferences for research and related discussion. It can also be used to cover expenditure for University approved journey (not reimbursed from other sources).
- Purchase of books, journals, subscription and professional membership.
- Purchase of teaching materials and teaching aids.
- Hosting of professional visitors.
- Any other expenditure as permitted from the U.D.F.
- Payment for the project of Students/faculties looking for filed for patent.
- The Vice Chancellor will reserve the right to use the fund of U.D.F. as per the requirements and urgency in the University.

The amount of I.D.F. will be utilized by the concerned Institute where consultancy/testing work has been done with permission of Vice Chancellor. The remaining amount of I.D.F. excluding U.D.F. will be utilized in testing expenses as well as distribution of remuneration amongst University staff as per rule.

7- Norms for Distribution of Consultancy/Testing Fee

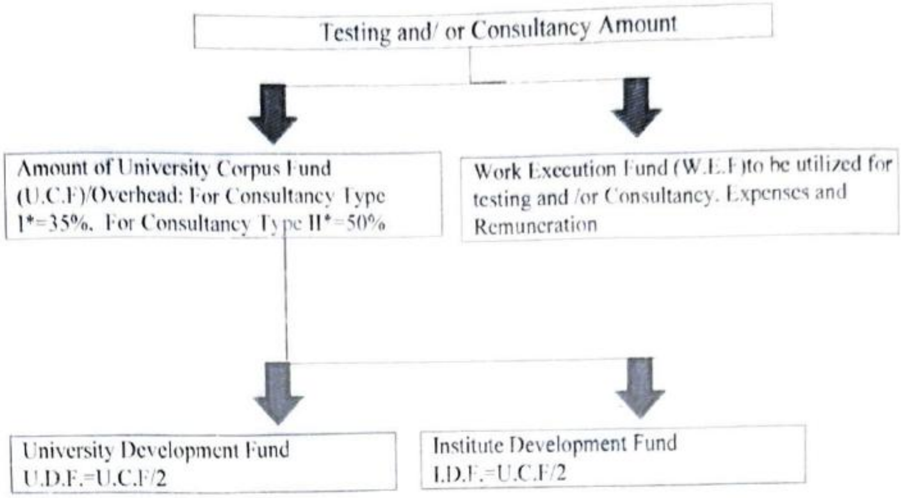

The W.E.F. as denominated in the figure will be expended by the PI as in flow chart following the applicable rules of University.

8- Distribution of Consultancy Fee in UNVERSITY CORPUS FUND-

The principal amount will be deposited in concerned bank account of the University for any type of testing and consultancy.

S.N.	Nature of the Project	Type of Consultancy	Total Project Cost (A)	U.C.F/Overhead (B)	Distribution /Remuneration (C)=(A-B)
1-	Consultancy/Testing	Type-I	X	0.35X	0.65X
2-	Consultancy/Testing	Type-II	X	0.50X	0.50X

Note –a) Type-I Consultancy /Testing includes Sponsored research project from Government agency, where University Corpus Fund will be waived off while for such projects from private organizations or industry, U.C.F. will be charged at par with the Type I consultancy. Other consultancy / Testing project will be inclusive of inspections/Technical Education visits. Individual consultancy based on expertise requirement of any individual for project, and conduction of courses with industry. If the course is organized by the University then 0.25X share will be transferred to the industry while 0.75X share will be transferred to the University and if the course is organized by industry then 0.25X share will be transferred to the University while 0.75X share will transferred to industry concerned or as decided by the University from time to time with approval of Vice Chancellor.

b-) Type-II Consultancy includes Testing of materials, or any other consultancy involving University's facilities.

c-) Category of any other work which is not included in the above mentioned will be decided by T &C committee.

9-Terminology-

- Project cost refers to the expenses incurred by the PI for the duration of the project. It includes remuneration, equipment, salaries, travel consumables, contingency etc.
- Overhead refer to the payment due to the University from the approved grant received from the funding agency/organization/industry.
- Sponsored research project refers to one in which the PI carries out original research such projects generally do not have a provision for payment of remuneration.

Testing refers to a very limited duration activity involving Laboratories/Workshop of the University.
The GST or any other taxes, as applicable or required to be paid for all consultancy projects.

10 -Details for calculation of overhead-

- **Sponsored Research Projects-** Proposals submitted for sponsored research must show overhead of 25% on the project cost. (Example- If the project requirement is X then overhead would be .25X and the total budget would be 1.25X).

- **Consultancy Testing Projects-**At the stage of proposal submission the budget will reflect-

  Project cost (X) includes, i.e. X=Project expenses + Overhead (XI)
  Overhead at 25% (XI=0.35X) for Type I consultancy.
  Overhead at 50% (XI=0.50X) for Type II consultancy.

  Goods and service Tex (GST) @ 18% (for example) (X2=0.18X), which is subjected to periodic revision by the Government of India.

  When consultancy/testing fee is received from the funding agency the following procedure will be followed-
  At the first instance, GST is deducted (18% of X) (subject to change by the Government from time to time). The University overhead (as above the different types of consultancy) is transferred to University Corpus Fund. The balance fund will be distributed the associated PI and staff as per the approved rules.

- **Courses-** For the short term courses, conferences, workshops, and symposia, 25% of the total receipts (Registration as well as grants) will be transferred to the University Corpus funds, 70% will be consumed by PI for expenses and distribution among team members.

11- Payment of Remuneration-

For Type -1 Testing and/ or consultancy, the norms for calculation of various percentages for distribution will be as followed-

1- **Total fee received from the client= A**

- Amount paid to U.C.F. (University Campus Fund)=0.35A
- Remaining amount (F)=0.65A
- Total expenditure on the project= E
- Saving =S=F-E
  - Amount to be distributed amongst the investigators = S

2- **Distribution of S-**

- Amount to be distributed among investigators (S)=0.70S
- Amount to be distributed to concerned Head of Department=0.0025S
- Amount to be distributed Staff of concerned Department =0.120S
- Amount to be distributed to the Director of the Institute =0.010S
- Amount to be distributed The office of the Director Establishment Accounts of the Institute =0.010S
- Amount to be distributed to The Finance Controller 0.0025S
- Amount to be distributed to The Registrar= 0.0025S
- Amount to be distributed to staff of V.C Secretariat , Registrar, Establishment and Finance and account Section = 0.090S
- Amount to be distributed in Staff Welfare Fund = 0.0625S

For Type -II Testing and/ or consultancy, the norms for calculation of various percentages for distribution will be as follows-

Total fee received from the client= B

- Amount paid to U.C.F. (University Campus Fund)=0.50B
- Remaining amount (F)=0.50B
- Total expenditure on the project= E
- Saving =S=F-E
- Amount to be distributed amongst the investigators = S

3- **Distribution of S-**

- Amount to be distributed among investigators (S)=0.60S
- Amount to be distributed in office and laboratory staff =0.20S
- Amount to be distributed to concerned Head of Department=0.022S
- Amount to be distributed to The Director of the Institute =0.02S
- Amount to be distributed The office of the Director, Accounts and Establishment of Institute =0.01S
- Amount to be distributed to The Registrar= 0.01S
- Amount to be distributed to The Finance Controller = 0.01S
- Amount to be distributed to staff of V.C Secretariat, Registrar, Establishment and Finance and account Section = 0.08S
- Amount to be distributed in Staff Welfare Fund = 0.05S

Note-

1- The distribution between Class III and Class IV employee of particular amount has to be done with 70:30 ratios subject to limit of the 75% of the gross salary received by an individual. In case, there is no regular Class IV or Class III employee is a section/department, the excess remuneration amount will go in Staff Welfare Fund.

2- In case, Registrar/Pro Vice Chancellor/Vice Chancellor performs Testing & Consultancy work for the University, he will receive the due remuneration as applicable to PI.

3- The rule of distribution will be applicable for all the payments due from the date of approval of this or its amendment as the case may be in the Executive Council.

4- In all the cases, the payment of remuneration will be given only to employees of the University.

5- In Case of University, the role of Director of Institute will be performed by the Chairman T&C Committee.

12- **Total Amount of Remuneration from Consultancy-**

The total remuneration to be received by an individual from Consultancy/Testing work will not exceed 75% of his gross salary received during the financial year. In such case where the PI is supposed to involve in any consultancy due to his expertise in any field and his total income from all consultancy work exceed the limit of 75% gross salary the prior approval of Vice Chancellor will be required. If the total remuneration payable to the staff member exceed the prescribed limit, without approval of University (Vice Chancellor) the excess amount will be deposited in the University Corpus Fund.

13- **General Conditions-**

- Any guideline further needed for operating consultancy project or any dispute arising in the University will be framed/solved by the T&C committee with the approval of Vice Chancellor.
- Individuals or departments or/ Institutes may take up consultancy work only after taking approval of the Vice Chancellor. The report of the consultancy project will be signed by the investigators and countersigned by the head of department and the report of the individual consultancy project will be signed by the Principal Investigator but kept in the record of the Institute.
- For project involving only site visits for consultation work and /or personal discussion, fee may be charged on per day basis at mutually acceptable rate subject to a minimum of Rs. 5000/- per man day, excluding the day spend on travel.
- For technical and other staff, making only site visits outside the scope of ongoing consultancy project, fee may be charged on per day basis at minimum of Rs. 1000/- per man day.
- The PI may, with the prior permission of the Vice Chancellor avail the service of person not in the University/Institute to save as Investigators, provided the HOD certifies that the services of a nature for which the expertise is not available in department/ Institute/University.
- The PI is authorized to associate any regular faculty\ contractual faculty/staff of the University with remuneration payable up to 20% of the share of PI.

- No consultancy project from any other agency can be taken up for an amount less then Rs. 25000/-. This limit may be reviewed from time to time by T&C committee and as approved by the Vice Chancellor.
- Duty leave will be admissible for consultancy work for 15 working days in a session For absence beyond 15 days for consultancy work, leave as due will be taken by the staff /faculty member. Any absence from the headquarter in connection with the consultancy approved by the testing & consultancy (T&C) committee will be with the prior approval of HOD of concerned department and Director of the Institute concerned.
- When a faculty member is approached for the consultancy work, he will be the principal invigilator. If he does not wish to be the Principal Invigilator, the Vice Chancellor will approve a suitable person as the PI on recommendation of Director of the Institute.
- The P.I who is due to retire from University service will identify a new P.I for the consultancy project at least three months before his/her retirement and transfer his responsibilities to him. .
- A copy of all reports submitted to the client firm will be filled in the department/Institute.
- The most expeditious and convenient mode of travel should be used for the consultancy work, to minimize period of absence from the University.
- All legal action will be subject to the jurisdiction at Civil Court at location of the University in Dehradun.
- In Case any legal dispute arise between the invigilator(s) and the client such that the invigilator(s) are in any way, held responsible to make good the losses occurred by the Client, such liability will be restricted to a maximum limit which will be calculations follows-

  Maximum Liability = The total amount charged for the project – total expenditure on the project.

VEER MADHO SINGH BHANDARI

UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY

Dehradun, Uttarakhand-248007, INDIA

Ordinance

for

Master of Technology (Part Time) Programme

M.Tech. PART-TIME

(w.e.f. 2023-24 and onwards)

This Ordinance is for 3 years part time Master of Technology (Part-Time) programme of six semesters.

1. Admission:

1.1 Admission to first year of M.Tech (Part-Time) three years part-time programme will be made as per the rules prescribed by Academic Council of VMSB Uttarakhand Technical University, Dehradun.

1.2 Admission on migration of a candidate from any other University to this University is not permitted.

2. Eligibility:

2.1. The minimum qualifications for admission to M.Tech (Part-Time) programme will be as per AICTE norms approved by Academic Council of the University.

2.2. The minimum qualification and experience for admission to M.Tech (Part-time) programme shall be as follows:

(a) Qualification as per clause 2.1 above and
(b) Minimum two years working experience in any Organization/Institution.
(c) Presently working in any Organization/Institution at a distance of not more than 50 Kilometers from the Institute.
(d) For General/OBC candidates 60% marks in B. Tech/BE or equivalent (Civil/Electrical/Mechanical/Industrial/Chemical/Electronics/Computer).
(e) For SC/ST candidates 55% marks in B. Tech/BE or equivalent (Civil/Electrical/Mechanical/Industrial/Chemical/Electronics/Computer).
(f) Candidates having 60% marks and valid qualified GATE score for General/OBC candidates and 55% of marks and valid qualified GATE score SC/ST candidates will be given preference in admission.
(g) NOC from the employer.

2.3. Direct admission on vacant seats at institution/college level.

The eligibility criteria for direct admission/sponsored admission on seats remaining vacant after counseling may be filled as notified from time to time by University.

2.4. Academic Council shall have power to amend or repeal eligibility criteria laid down on adopting new guidelines of AICTE/UGC.

3. **Duration of Course:**

3.1. M. Tech (Part Time) is 3 year (6 semesters) programme. There are two regular semesters in a year. The semester that usually begins in July (July to November/December) is known as the Odd Semester and the semester that usually begins in December/January (December/January to May) is known as the Even Semester. Academic session may be scheduled in the winter/summer vacations as well.

3.2. Maximum time allowed for a candidate admitted in M.Tech (Part-Time) for completing M.Tech (Part-Time) is 5 years, failing which he/she shall not be allowed to continue his/her M.Tech. (Part-Time) Degree.

4. **Curriculum:**

4.1. The 3 years curriculum has been divided into 6 semesters and 1 year curriculum is divided into 2 semesters. It shall include lectures, tutorials, practical, seminars, project, dissertation etc. required for the degree course as prescribed in the scheme and instructions issued by the University from time to time.

4.2. The curricular and co-curricular along with extra-curricular activities may be prescribed by University if AICTE guide lines are prescribed on the issue.

4.3 **Curriculum Structure**

The University follows a specialized credit based semester system. Every Programme will have a specific curriculum for all semesters (Semester 1 to Semester 6) with a syllabi consisting of Theory, Practical, Project work, Dissertation etc. as given below and shall be in accordance with the prescribed syllabus. The subjects shall be covered through lectures, Tutorials, laboratory classes, seminar, projects work, dissertation etc. as prescribed by university. The curriculum structure comprises of broad segments as tabulated below.

Knowledge Segments	**Credits**
Mathematics	5
Professional core courses	19
Professional Electives	13
Open Electives	3
Research Methodology and IPR	2
Seminar	3
Project	6
Dissertation	21
Total academic credits for M.Tech.(Part-Time) degree	**72**

5. **Attendance:**

Every student is required to attend all the lectures, practicals and other prescribed curricular and co-curricular activities. The attendance can be condoned on medical ground or for other genuine reason beyond control of student but the attendance can be condoned only up to 20% only. Attendance will be deciding criteria for permission to appear in the examinations. It will be applicable subject wise and attendance will be counted from the date of admission in the course and first teaching class begins of the subject. The percentage of attendance will be estimated on the total classes held and the classes attended by the candidate.

संलग्नक - 07

VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY

(Formerly Uttarakhand Technical University, Dehradun Established by Uttarakhand State Govt. wide Act no.415 of 2005)

Suddhowala, PO-Chandanwadi, Premnagar, Dehradun, Uttarakhand (Website-www.uktech.ac.in)

ORDINANCE

For

Master of Technology Programme (Part-Time)

(For admission in session 2023-24 and onwards)

6. **Examination:**

6.1. The performance of a student in the semester shall be evaluated through continuous class assessment and end semester examination. The continuous assessment shall be based on class tests, assignments, tutorials, quizzes, viva voce and attendance. The marks for continuous assessment shall be awarded at the end of the semester (sessional marks). The end semester examination shall be comprised of written papers, practicals, viva voce, project work, design report, seminar and dissertation evaluated by supervisors and external evaluators with open defense.

6.2. Scheme of examination will be provided on each aspect and accordingly statement of marks will be prepared for records and award of M.Tech (Part-Time) degree.

6.3. The marks obtained in a subject shall consist of marks allotted in end semester theory paper, practical examination and sessional work. The grade will be awarded based on marks obtained as per Clause 10. The "F" grade denotes the failure in passing respective subjects and student has to make another attempt to pass the subject as per the provisions of this Ordinance.

6.4. The minimum pass marks in each theory subjects shall be 50% (including sessional marks) with minimum 40% in each theory papers in the end semester examination. If there is no sessional mark prescribed for theory papers then 50% will be minimum passing marks.

6.5. Project/Practical shall be 50% minimum marks to be declared pass and dissertation 70% marks will be minimum to be declared pass.

6.6. Aggregate of marks obtained by candidate to declare pass in M.Tech (Part-Time) shall be 50%.

7. **Unfair Means:**

7.1. If unfair means is adopted by the M.Tech (Part-Time) student, the subject evaluation will be cancelled and candidate has to reappear in the examination, whenever conducted by the University.

7.2. Dissertation must be candidates own work written with similarity index being less than 20% as per similarity check software prescribed by the University. If Plagiarism is found in the dissertation with sufficient proof, the M.Tech (Part-Time) degree will be made null and void at any stage.

8. **Grace marks:** In M.Tech. (Part-Time) grace marks will be nil.

9. **Structure of Grading of Academic Performance:**

The following shall be the structure of grading for academic performance of the students:

9.1 **Award of Grades:**

Students obtaining grades O to P, shall be declared pass. Students failing in subject will be awarded F grade. The grades shall be decided on the aggregate of evaluation of all the components like: -
Three written tests: CT-1, CT-2 and End Semester Examination, Assignments, Quizzes, Tutorials, Practicals and regularity in attendance etc.
Practical, Project and dissertation shall be evaluated & graded as per guideline.

Structure of Grades and Grade Points:

Grades	Grade Point (GP)	% of Total Marks obtained in the course
O-Outstanding	10	90%and above
A+-Excellent	9	85%and above but less than 90%
A-Very Good	8	80%and above but less than 85%
B -Good	7	70%and above but less than 80%
C -Average	6	60%and above but less than 70%
P-Pass	5	50%and above but less than 60%
F-Fail	0	Less than 50%
AB- Absent	-	Absent

The "W" grade is awarded to a student if he/she is allowed to withdraw for an entire Semester only if he/she has been on authorized absence from the Institute/University on medical grounds for a period exceeding four weeks and informed to the University in time. The "I" grade is awarded to a student who is unable to complete the course.

9.2 Evaluation of Performance:

The performance of a student will be evaluated in terms of two indices, viz., the Semester Grade Point average (SGPA) which is the Grade point Average for a semester and Cumulative Grade Point Average (CGPA) which is the Grade Point Average for all the completed semesters at any point in time. The SGPA is calculated on the basis of grades obtained in all courses, except audit/non-credit courses, registered in the semester.

$$\text{SGPA} = \frac{\sum_{i=1}^{s} C_i G_i}{\sum_{i=1}^{s} C_i}$$

where C_i = Credits of the registered subject

G_i = Grade point awarded to the student in the registered subject

s = Total number of registered subjects in the semester, except audit/non-credit courses. Here the failed courses are also accounted.

The overall Grade of a student in the program of study upto the end of a particular semester shall becalled Cumulative Grade Point Average (CGPA). CGPA shall be calculated on the basis of all grades, except audit courses, obtained in all completed semesters as follows:

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{i=1}^{n} C_i G_i}{\sum_{i=1}^{n} C_i}$$

where C_i= Credits of the registered subject

G_i= Grade point awarded to the student in the registered subject

n = Total number of registered subjects, except audit/non-credit Courses. Here the failed courses are also accounted.

The SGPA and CGPA will be rounded off to 2 decimal points and reported in marksheet, transcripts, etc.

Conversion of Grade in to percentage: The performance of the students is measured in terms of CGPA (on a 10 point scale) as defined above. The equated percentage shall be equivalent to CGPA x 9.5.

Award of Division:

First Division - CGPA of 6.5 and above but less than 10 CGPA (First Division with Distinction will be awarded to those securing CGPA of 8 and above but less than 10 CGPA provided they pass all the examinations in first attempt)

Second Division- CGPA of 5 and above but less than 6.5 CGPA

Definition of Credit:

1 Hr.Lecture (L) per week	1 Credit
1 Hr.Tutorial (T) per week	1 Credit
2 or 3 Hours Practical (P) per week	1 Credit

Essential Credits for M.Tech (Part-Time) Degree: The credits essential for obtaining the M.Tech (Part-Time) Degree in a particular specialization is 72 credits for admissions in 3 year M.Tech (Part-Time) degree.

10. Earned Credits (EC):

The credits assigned to a course in which a student has obtained "P" (minimum passing grade) or a higher grade will be counted as credits earned by him/her.

11. Promotion:

11.1 A student has to usually earn a minimum 12 number of credits in a semester to be eligible to register for the new subjects offered in the next semester. But in odd semesters if this requirement is not met, the student is to be forewarned and allowed to continue to the next even semester. However at the end of even semesters this requirement will be strictly implemented as detailed in "Eligibility criteria for registering in higher semesters". Students who do not meet this requirement detailed in Table 1 is not permitted to register for new course in the higher semesters. They have to either register for appearing in examination of the failed course in normal semesters in which they are offered course(s).

Table 1: Eligibility Criteria for Registering in Higher Semesters for 3-year M.Tech. (Part-Time) Programme

Semester	Allotted Credits	Cumulative Credits	Minimum cumulative credits required to register for courses in higher semester
First	14(14+3*)	14	Not insisted
Second	08(08+3*)	22	22
Third	12 (12+3*)	34	Not insisted
Fourth	08 (08+3*)	42	42
Fifth	15	57	Not insisted
Sixth	15	72	--

Optional credit course to students and it is not mandatory to promote in the next academic year. The marks of these optional subjects will be displayed in mark sheet.

Faculty advisors (Head of Department to designate One Faculty advisor) shall monitor advice and support the students for this. Institute shall make necessary arrangement to inform the students about the minimum cumulative credits requirement to register for higher semester as in Table1.

11.2 The candidate shall appear in the theory papers which does not satisfy clasue11.1only two times after main examinations, otherwise has to leave the M.Tech (Part-Time) course.

11.3 There shall be no carryover in M.Tech (Part-Time) 3rd year.

11.4 Project/Dissertation duration will be one year and RDC (PG) will monitor the progress of the candidate on the topic at least two times before permission to write dissertation.

12 Evaluation of Dissertation:

12.1 Supervisor will submit at least three members expert list from relevant area with complete name & address and Head of Institution will designate one name outside the institute for evaluation of M.Tech. (Part-Time) dissertation and supervisor will evaluate independently.

12.2 If the mark is less than 70%, then candidate has to resubmit his/her dissertation for next evaluation.

12.3 The internal assessment marks will be awarded based on evaluation of progress made by student in the work at least three times in a semester. Each evaluation will be of equal weightage. Total internal marks will be sum of:

i)Progress review - 60%

ii)Supervisor assessment - 40%

12.4 There will be open defence of M.Tech (Part-Time) dissertation before external evaluator and any one of the two Professor/Associate Professor nominated by Head of Institution. The aggregate marks will be sum of marks awarded individually by External evaluator + Nominated internal teacher (Professor/Associate

professor) + Supervisor during viva-voce examination i.e. open defence. The marks distribution will be on the following basis

Quality of work	-	200
Report	-	100
Presentation	-	100
Viva-voce	-	50

12.5 It is compulsory for every student to submit/publish a research paper in SCI/Scopus/UGC indexed journal or national/ international conference before submission of thesis and also submit the similarity check report of originality being not less than 80% as per similarity check software prescribed by University.

13. Results:

The result of a candidate shall be declared on the basis of performance of both semesters of the same academic year by the University.

14. Award of Rank and Medals:

On the basis of final year result, the top three candidates in branch of M..Tech (Part-Time) shall be awarded rank according to their merit provided they pass all the examinations in first attempt in the minimum duration prescribed for the programme.

15. Cancellation of Admission:

The admission of a student at any stage of study shall be cancelled if:

He/She is not found qualified as per AICTE/State Government norms/Guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.

or

He/She is found unable to complete the course within the stipulated time as prescribed in Clause 3.2.

or

He/She is found involved in creating indiscipline in the Institution/ College or in the University.

or

The University can cancel the admission of any student who fails to submit the prescribed documents by the specified date or to meet other stipulated requirement(s). The University may also cancel the admission at any later stage if it is found that the student had supplied false information or suppressed relevant information while seeking admission.

The University reserves the authority to withdraw the degree conferred to a candidate on account of any discrepancy in the candidature observed at later stage.

16. Change of College:

As it is a specialized programme, hence change of college/institute shall not be permitted.

17. The Academic Council shall have the power to amend/relax any provision provided in the ordinance in any specific matter/situation subject to the approval of Executive Council of the University & such decision(s) shall be reported to the Chancellor of the University.

....

क्रम संख्या–98 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2023 ई0

आश्विन 25, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 372/XXXVI(3)/2023/45(1)/2023

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023' पर दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 25, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संलग्नक – 08

TED-EST/RETR/17/2022-XLI-A-I-Techn[illegible] ucation Department

/167507/2023

प्रेषक, संख्या 1383/XLI-A/23-25/22-ई-45510

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

तकनीकी शिक्षा विभाग देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2023

विषय: वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अधिनियम, 2005 में संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–372/XXXVI(3)/2023/45(1)/2023 दिनांक 17.10.2023 का संलग्नकों सहित अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा–2 में संशोधन किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–372/XXXVI(3)/2023/45(1)/2023 दिनांक 17.10.2023 की छायाप्रति संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन के उपरांत नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

Signed by Raman Ravinath
Date: 07-11-2023 17:28:23

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
3. निजी सचिव, मा. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड नैनीताल।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी., नई दिल्ली।
11. अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
12. कुलसचिव, हेमवती नन्दन गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल।
13. कुलसचिव, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून।
14. कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी।

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2023)

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2005) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

धारा 2 का संशोधन 2. वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 2 में,–

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

"(ख) अनुमोदित संस्था ' का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं विधि शिक्षा की संस्था से है।"

(दो) खण्ड (त्र) के पश्चात नया खण्ड (त्र त्र) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

"(त्र त्र) विधि शिक्षा ' का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, जिसे केन्द्र सरकार, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य नियामक परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करें।"

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

कारण और उद्देश्य

"वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" में विधि शिक्षा के संचालन हेतु वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री।

No. 372/XXXVI(3)/2023/45(1)/2023
Dated Dehradun, October 17, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2023' (Act No. 25 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12th October, 2023.

The Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2023

(Uttarakhand Act No. 25 of Year, 2023)

An

Act

Further to amend in the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Act, 2005 (Uttarakhand Act No. 5 of Year 2005)

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Seventy-Fourth year of the Republic of India as follows-

Short title and commencement	1.	(1)	This Act may be called the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2023.
		(2)	It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
Amendment of Section 2	2.		In Section 2 of the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Act, 2005,-
		I	Clause (b) shall be substituted as follows, namely:-
			(b) "Approved Institution" means an institution of Technical and Legal Education approved by the University/State Government.
		ii	After clause (j) a new clause (j j) shall be inserted as follows, namely:-
			(j j) "Legal Education" means such education, which the Central Government 'may in consultation with the Bar Council of India, University Grants Commission and any other regulatory council related to professional education, by notification in the Gazette, declare;"

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

Statement of objects and reasons

For conducting legal education in the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, amendment in Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Act, 2005 is necessary.

2- Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Subodh Uniyal
Minister

पी०एस०यू० (आर०ई०) 32 विधायी / 446–2023–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)